यदि खास तौर पर कोई जानकारी मिल जाय जहां पर इस प्रकार के प्रावधान हैं और उन पर अमल नहीं हो रहा है तो मैं निश्चित रूप से अमल करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा ।

SHRI PRABHAKAR B. KORE: Mr. Chairman, Sir, I would like to know from the hon. Minister whether the Government desires to establish Kendriya Vidyalayas to provide educational organisations by providing administrative and financial assistance with private organisations.

SHRI ARJUN SINGH: Sir, we rather welcome this. If any public enterprise or private enterprise wants to open Kendriya Vidyalayas under the CBSE, we would ,not only welcome it; we would rather say that that would be a step in the right direction. And there are many institutions which are being run by certain private and public sector undertakings.

Setting up of building material and technology Promotion Council

*403. DR. BAPU KALDATE:†
SHRIMATI IMIRA DAS:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Build ing Material and Technology Promotion Council has been set up without obtain--ing concurrence of the Ministry of Finance;

(b) whether it is also a fact that the post of Executive Director which is equivalent to the post of Additional Secretary has been created in the BMTPC without the approval of Ministry of Finance;

(c) whether the Executive Director in BMTPC has been appointed without getting clearance of Cabinet Committes on Appointments;

(d) whether the BMTPC has been provided accommodation in Nirman Bhavan and residential Government Quarters without approval of Cabinet Committee on Accommodation; and

(e) if so, what action Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISIRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (e) A Statement is laid On the Table of the Sabha.

Statement

(a) The Building Materials and Technology Promotion Council' (BMTPC) is a Government funded Society regisered under the Societies Registration Act 1860. It was set up with the approval of administrative Ministry and plan funds were provided with the approval of the Planning Commission.

(b) The post of Executive Director in BMTPC is not equivalent to the post of Additional Secretary to the Government of India. Since the Council is an autonomous registered society creation Of posts in a - particular grade in the society, is covered by its own rules and regulations.

(c) The appointment to the post of Executive Director does not fall within the purview of the Appointments Committee of Cabinet.

(d) and (e) The BMTPC has been only temporarily accommodated in Nirman Bhavan till such time as it acquires its own permises. The approval of Cabinet Commmittee on Accommodation is being sought for. The Council has secured off a space in another non-Governmental building presently ' under construction where it will more as soon as the premises is ready for occupation.

As per the existing Government's instructions, governing retention of general pool accommodation on appointment to a newly established organisation sponsred by Government, only four employees of the Council have been allowed to retain the general pool accommodation for two years.

† The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Bapu Kaldate.

डा० बापू कालदाते : सभापति जी, यह सारा उत्तर पढ़कर इसलिए खुशी है कि इसमें जो-जो खामियां हैं, उसका पता लग गया । मुझे यह आश्चर्यजनक उत्तर लगता है क्योंकि इसमें पैसा आयेगा प्लानिंग कमीशन की अप्रूवल से और जगह देगी सरकार निर्माण भवन में, उनके जो पदाधिकारी हैं उनको जगह देंगे आप, लेकिन अप्वाइंटमेंट का अधिकार आपको नहीं है । इसके लिए आप कहते हैं यह तो रजिस्टर्ड सोसायटी है इसलिए वहां किसको अप्वाइंट करना है, उसका अधिकार आपको नहीं है । पैसा देंगे, घर देंगे, दफ्तर के लिए जगह देंगे, यह सारा आपका काम है लेकिन वहां कौन लोग नियुक्त करेंगे, इसका अधिकार आपके हाथ में नहीं है । मुझे इसका डर है कि यह तो ओल्ड ब्वायज क्लब बन गया है जिनको मन आये उनको अप्वांइट करो । क्या प्रोसीजर है । व्हाट आर दि रूल्स अंडर विच दे हैव बीन अप्वांइटेड । आप पैसा देते रहे और वे किसी को भी अप्वांइट करें, यह तो नहीं चलेगा । मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं क्यों कि आप उस सदर हैं । यह जो बी.एम.टी.सी. पी. है इसकी आप सबर हैं। मुझे इसमें आश्चर्य लग रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है । सारा कुछ तो आप उनको दें, लेकिन उनके अप्वाइटमेंट के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है, यह बात हमारी समझ में नहीं आती है । इसमें यह भी बात है, जो आपने डी एंड ई में लिखा है कि आपने उनको जगह दी तो क्यों नहीं आपने पहले कैबिनेट का अप्रुवल मांगा ? आप यह कह रही हैं कि हम इसके लिए कैबिनेट के पास अप्रुवल के लिए गए हैं, यह कोई आज की बात नहीं है । बी.एम. टी. पी. सी. 90 में बन गया है । बी.एम.टी.पी. सी. नब्बे में हो गया, आज तक दो साल हो गए हैं, आपने आज तक अप्रुवल क्यों नहीं मांगी ? आपने जब उनको जगह दी तब क्यों नहीं मांगी । मेरे दो स्पेसिफिक क्वेश्चन इसमें हैं । मुझे डर लग रहा है जैसा कि मैंने कहा ओल्ड ब्वाइज क्लब, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं क्योंकि अफसर लोग जिनको नियुक्त किया गया है उनको यहां आने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा । लेकिन मेरे पास यह नामों की फेहरिश्त है । वह फेहरिश्त इस बात की आशंका पैदा करने वाली है कि यह दोस्त लोगों का क्लब बन गया है । कोई किसी का रिश्वदार है, कोई किसी का पुराना सेक्रेटरी या प्राइवेट सेक्रेटरी है, जो कि रिटायर हो गये हैं । रिटायर लोगों को आप ले आये हैं । आप रिटायर लोगों को क्यों लाये हैं ? जो 5–10 अप्वाइटमेंट हुए हैं इसमें रिटायर कितने लोग हैं ? क्यों लिया है उनको ? क्योंकि अप्वाइंटमेंट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उनके हाथ में है, चाहे किसी को भी बुलाओ, चाहे किसी को भी बिठाओ । अपनी मनमर्जी का कारोबार है और पैसा देंगे, आप यह ठीक नहीं है । इसलिए मेरा सवाल यह है कि इसके लिये रूल्स और प्रोसीजर क्या है..... (व्यवधान)...

श्री सभापति : ही इज आस्किंग क्वेश्चन । प्रश्न पूछ रहे हैं ।

डा० बापू कालदाते : मैं यही कह रहा हूं, माई क्वेश्चन इज वेरी सिम्पल ...(व्यवधान)... सुन लीजिए ।

MR. CHAIRMAN: Don't disturb him. Otherwise, more time will be consumed.

डा० बापू कालदाते : मेरे दो क्वेश्चन हैं । मेरा पहला क्वेश्चन यह है कि यह बी.एम.टी.पी.सी. जिसको आपने निर्माण भवन में जगह दी, इसका अप्रूवल आपने पहले क्यों नहीं लिया ? अगर आप अप्रूवल मांग रही हैं तो कब आपने मांगना शुरू है किया है और कब तक अप्रूवल आने की संभावना है ? दी यह है कि जो इनके रूल्स हैं, इस सोसाइटी के, जो रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाई है, क्या इसके रूल्स आप सदन के सभा पटल पर रखने के लिए तैयार हैं ?

श्री एन०के०पी० साल्वे : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अंग्रेजी में बोलें तो समझ में आये, अंग्रेजी क्या उनकी हिन्दी से अच्छी है ?

श्री सभापति : हिन्दी से बिल्कुल। उनकी मराठी सबसे अच्छी है, उसके बाद अंग्रेजी और उसके बाद हिन्दी ।

डा० बापू कालदाते: मैं माहिर नहीं हूं, न अंग्रेजी में न हिन्दी में ।

श्री प्रमोद महाजन : अंग्रेजी उनकी तमिल से अच्छी है, इसलिए वह कह रहे हैं।

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI SHEJLA KALOL): Sir, the question posed to us is about the accommodation that is. required for this organisation. I would like to inform the hon. Member that this organisation is having its own accommodation constructed in the Habitat Centre in Lodhi Colony for which a fund of Rs. 1 crore has been provided so far. As it was organised and there was no place to begin with some room has been given to them in some part of the Nirman Bhavan. That is correct. But their offices are under construction.

डा० बापू कालदाते: आपने अप्रूवल क्यों नहीं मांगा ? आपने लिखा है कि हम अप्रूवल के लिए लिख रहे हैं । यह तो ठीक बात है उनको जगह चाहिए (**व्यवधान**)

श्रीमती शीला कौल : अगर अब मांग लिया तो देर आयद दुरुस्त आयद । आपने राय भी दी है (**व्यवधान**)

श्री सभापति : अब रास्ते पर आ रहे हैं।

डा० बापू कालदाते : रूल्स का क्या हो गया ?

Are you going to lay on the Table of the House the rules and procedures of appointments?

श्री सभापति : नियुक्तियां किस प्रकार से करते हैं, क्या कुछ रूल्ज हैं। आप तो करती नहीं हैं (**व्यवधान**)

श्रीमती शीला कौल: आपको यह पता है कि यह एक सोसायटी बनाई गई है ।

It is on the same pattern of the Council of Scientific and Industrial Research.

उसके पैटर्न पर बनाई गयी है जैसेकि काउंसिल, आफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च बनती है, उसी के तरीके से यह भी बनाई जा रही है । जो नियुक्तियां होती हैं उसको एग्जिक्यूटिव कमेटी करती है । उसके पैटर्न पर है । यह भी एक साइंटिफिक बाडी बनाई गई है न कि यह मिनिस्ट्री के अंडर एक छोटा आफिस है । इसलिए यह एक सेप्रेट (**व्यवधान**)

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई दम नहीं है ।

डा० बापू कालदाते : अब सही सवाल यह पैदा हो गया है । सरकार के पास दो संगठन हैं एक है एन.बी.ओ. जिसकी प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक 1945 में स्थापना की गई थी । गत कई वर्षों से यह काम करता आ रहा है । अब इसका काम और जो बी०एम०पी०टी० सी० का जो काम है, दोनों के काम में मुझे कोई फर्क नहीं आ रहा है । बी.एम. पी.टी.सी. बिल्डिंग मेटिरियल और टेक्नोलोजी प्रोमोशन करेगा । अब यह जो किताब मेरे हाथ में एन०बी०ओ० की है इसमें जो काम होते हैं इसमें भी बिल्डिंग्स मेटिरियल और टेक्नोलोजी प्रोमोशन की बात लिखी है । तो मेरा सवाल यह है कि वाई डुप्लीकेशन आफ एजेंसीज, यह मेरी समझ में नहीं आता । एन०बी०ओ० में 1988 से आपने डायरेक्टर की नियुक्ति नहीं की । जो बी०एम०पी०टी०सी० में अप्वाइंट किये हैं वह आप एन०बी०ओ० से ले रहे हैं । आपके मन में क्या है, आप साफ कर दीजिये, क्या आप एन० बी०ओ० को वाइंड-अप करना चाहते हैं, उसको बर्खास्त करना चाहते हैं ? अगर बर्खास्त करना चाहें तो ठीक रहेगा लेकिन 10-15 अफसर इधर से और 10-15 अफसर उधर से.. (**व्यवधान**)

श्री सभापति : आपका प्रश्न यह है कि एन०बी०ओ० को बर्खास्त करें **(व्यवधान)**

डा० बापू कालदाते : अगर बर्खास्त करना चाहते हैं तो जो लोग होंगे उनके बारे में आप क्या करना चाहते हैं ?

श्रीमती शीला कौल : सर, हमारा कोई इरादा नहीं है, किसी को बर्खास्त करने का और इसमें जो एन०बी०ओ० से बी०एम०पी०टी०सी० में जाना चाहते हैं धीरे धीरे लिये जायेंगे क्योंकि इसमें उनका भी थोड़ा थोड़ा हक बनता है । लेकिन यह जो हमारे लोग इसमें हैं हम चाहते हैं कि जो नये लोग बी०एस०पी० टी०सी० में आयेंगे नये आइडियाज के आयेंगे और नयी टेक्नोलोजी शुरू हो रही है उसके अन्दर हमें मदद मिलेगी । नये ख्यालात आयेंगे और नये ढंग से काम करेंगे । यह कहना कि हम कंडम करते हैं किसी को यह सही बात नहीं है । इनको हम धीरे धीरे लेंगे ।

As times go on we shall try to adjust people is they become surplus.

डा० बापू कालदाते : हलाल मत करिये, झटका दे दीजिये । यह धारे-धीरे क्या जल रहा है **(व्यवधान)**

श्री एन०के०पी० साल्वे: यह आपकी फिलासोफी है **(व्यवधान)**

SHRIMATI iMIRA DAS: Mr. Chairman. Sir, the National Building Organisation is a 38-yea$_r$ old Government organisation and about 200 people are working there. What was the necessity fo$_r$ winding it up? Now, of course. Madam Minister has admitted that she is not going to wind it up. Is there any proposal? What is the reason behind it? I would like to know from the hon. Minister what the performance and achievements of B.M.T.P.C. have been *vis-a-vis* N.B.O. Part (b) of my question is, what procedure was alopted in appointing the Executive Director in the BMTPC. I also want to know whether it was advertised in the newspapers or not.

SHRIMATI SHEILA KAUL: Sir, I would like to say a little briefly on how the thing came up. The proposal was to set up an autonomous body. It was discussed in the Inter-Ministerial meeting in March, 1989. There were some financial institutions like National Housing Bank, Unit Trust of India, the State Bank of India and Housing Development Finance Corporation who favoured the establishment of the organisation as an autonomous body. Even our draft National Housing Policy of 1990 stipulated that an integrated approach is required in the field of transfer of technology and commercial production, which the NBO was not doing, of newly developed building material and their development. A question has also been asked about how Council was set up. The proposal for setting up the council was finalised in consultation with the Ministry's financial adviser. The planning Commission provided funds for the council which were projected in the Budget. So everything has been done according to the way it should have been done. It was further approved by the Urban Development Minister on 2-4-1990.

SHRIMATI MIRA DAS: The NBO was doing commendablg work for the low cost housing. T don't find any reason to closing the organisation.

SHRIMATI SHEILA KAUL: You want the NBO to be closed down?

SHRIMATI MIRA DAS: I don't want the.....

SHRIMATI SHEILA KAUL: What is your suggestion?

MR. CHAIRMAN: She wants to know what war, the need of creating a new organisation.

SHRIMATI SHEILA KAUL: If the NBO was not doing the work in the way it should have been with the new technical system that is there and the.... *(Interruptions).*

SHRI MENTAY PADMANABHAM: They can have a cell of the NBO. Why have an organisation?

SHRI HIPHEI; I want to know whether there has been any objection from the Ministry of Finance for setting up this Council. If there is no objection then why should it shuttle between the two Ministries. I want to know whether there has been any objection from the Finance Ministry for setting up the BMTPC.

SHRIMATI SHEILA KAUL: No.

MR CHAIRMAN: She says, there is no objection.

SHRI SIKANDER BAKHT: Sir, this is another example of blatantly creating multiplicity of... (व्यवधान)

वक्त तो नहीं है। मगर क्या करें। मल्टीप्लिसिटी आफ अथारिटीज हैं और जो जवाब है इसमें साबित करने की कोशिश की गयी है कि इस नयी आर्गेनाइजेशन का कोई ताल्लुक पुरानी आर्गेनाइजेशन से नहीं है। खैर, मेरे पास वक्त नहीं है लेकिन मैं सवालात पूछता हूं। मुझे तफसील में बहुत कुछ कहना था.. (व्यवधान)

وقت تو نہیں ہے - مگر کیا کریں - ملٹی پلسٹی آف اتھارٹیز ہیں اور جو جواب ہے - اسمیں ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس نئی آرگنائزیشن کا کوئی تعلق پرانی آرگنائزیشن سے نہیں ہے- خیر - میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن میں سوالات پوچھتا ہوں - مجھے تفصیل میں بہت کچھ کہنا تھا - .... (مداخلت)...]

I want to know whether the officers of the BM.PTC were lent by the Ministry of Urban Development. If so, have they retained their pay position? Do they have the lien to come back to their parent organisation? Whit have been the criteria of the selection of these officers who have been lent to the BMTPC? What out-of-turn advantage the officers who have been lent to the BMTPC have obtained against their colleagues in the present organisation?

SHRIMATI SHEILA KAUL: Sir, I think, I need, with your permission, a little time to give right answer to the hon. Member.

श्री सिकन्दर बख्त : आप बशौक टाइम ले लें। मुझे सिर्फ एक बात बता दें। ये तमाम के तमाम बयानों में गवर्नमेंट फंडेड है, एप्रूवल्स का जिक्र सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री का है।

†[شری سکندر بخت : آپ بیشک ٹائم لے لیں - مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ یہ تمام کے تمام بیانوں میں گورنمنٹ فنڈیڈ ہے- اپروول کا ذکر صرف ایڈمنسٹریٹو منسٹری کا ہے -]

Appointment of Directors does not fall within the purview of additional accommodation in Nirman Bhavan....

सबसे बड़ी बात यह है कि आपने आखिरी पैराग्राफ में कहा है—

†[سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے آخری پیراگراف میں کہا ہے-]

Four employees of the Council have been allowed to retain. What do you mean by 'retain'?

श्री सभापति : एम०पी० जनाराज हैं कि उनको जगह नहीं मिल रही है। आपने दूसरों को दे दी है।

श्री सिकन्दर बख्त : यहां जनरल पूल में अकामोडेशन नहीं है, मल्टीप्लिसिटी आफ अथारिटी चल रही है यानी माफ करेंगे, बिल्कुल मुगलतानाशाही का बाजार गर्म है।

†[شری سکندر بخت یہاں جنرل پول میں اکوموڈیشن نہیں ہے - ملٹی پلسٹی آف اتھارٹی

[ ]Transliteration in Arabic Script.

چل رہی ہے ۔ یعنی معاف کریںگے بالکل مغلیہ قتاشاہی کا بازار گرم ہے ۔

श्री एन० के०पी० साल्वे : यह पहली दफा ही रहीं हैं ।

श्री सिकन्दर बख्त : मैं सही बात कह रहा हूं ।

†[شری سکندر بخت : میں صحیح بات کہہ رہا ہوں ۔]

श्री एन० के० पी० साल्वे : यह इस मंत्रालय की परम्परा रही है ।

SHRIMATI SHEILA KAUL: There is a rule. They can do it for a certain length of time. They can do it.

MR. CHAIRMAN: Question No. 404.

Dangerous buildings in Delhi

*404. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have prepared any list of dangerous buildings in Delhi;

(b) if so, whether the notices to demolish these buildings have been issued to the owners of such buildings:

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) As the Government prepares list in respect of buildings owned by it, no such notices are issued. However, under the Delhi Municipal Corporation Act notices are issued in respect of buildings which are found dangerous or are in imminent danger of collapse. Last year, the Municipal Corporation surveyed more than 3.81 lakh buildings and three were declared as dangerous.

The NDMC has reported that in respect of buildings considered dangerous, notices are issued under the Punjab Municipal Act for carrying out repairs.

The Delhi Cantonment Board has reported that no list of dangerous buildings in the area under management of Delhi Cantonment Board has been prepared.

(d) Does not arise.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Sir, as you see from the reply, the Ministry has taken this matter casually. The rainy season is coming and the middle-classes and the ordinary people are going to be affected. I would like to know from the Minister whether he is aware that dilapidated buildings are not only old building but even new DDA buildings have been found to have collapsed because they did not have proper foundation or they did not have the technique for geo-soil investigation. They do not have the instrument. Is the Minister aware that new DDA buildings have collapsed upon construction even before occupancy in some cases or one month after occupancy?

SHRI M. ARUNACHALAM: Si, generally dangerous buildings are being declared ,(i) under failure of foundation (ii) under failure of super-structures like column beams, slabs etc. and also inadequacy of fire safety measures.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: I asked whether he is. . .

SHRI V. NARAYANASAMY: He is coming to your question. . .

MR. CHAIRMAN: He is interested in the DDA buildings.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: He is filibustering for time.

SHRI M. ARUNACHALAM: If anything is brought to our notice, definitely we will look into it.

MR. CHAIRMAN: He is asking about DDA, the collapse of DDA buildings, Delhi Development Authority buildings.

† [ ] Transliration in Arabic Script.